www.vidarbhakibaat.in

Post Reg. No. RNP/NPCITY /169 /2015-2017

प्रखर... मुखर... स्वर

विदर्भ की बात

● वर्ष 17 ● अंक 95 नागपुर, बुधवार, 1 मार्च 2017 ● पृष्ठ 8 ● मूल्य ₹ 2

सुप्रभात

ब्लाइंड टी-20 विश्वविजेता टीम ने प्रधानमंत्री से की मुलाकात

नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मंगलवार ब्लाइंड क्रिकेट टी-20 की विश्वविजेता टीम के सदस्यों ने मुलाक़ात की। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने भारतीय क्रिकेट टीम से खिलाड़ियों को उनकी बेहतरीन उपलब्धि पर बधाई दी और भविष्य में इससे भी बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके कौशल और एकाग्रता की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनकी ये सफलता लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बनेगी। टीम के खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री को एक मौके पर बैट,बॉल और टीम की जर्सी भेंट की। बता दे कि प्रधानमंत्री ने इससे पहले बीते रविवार को रेडियो पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम मन की बात में भी भारतीय टीम को ब्लाइंड टी-20 का विश्वकप जीतने पर बधाई दी थी। भारत की टीम ने अपनी चिर प्रतिद्वंदी टीम पाकिस्तान को नौ विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार खिताब पर कब्जा किया था।

महज 15 मिनट में पूरा हुआ गोवा विधानसभा का विशेष सत्र

पणजी

गोवा में विधानसभा चुनाव बीतने के करीब महीने भर बाद विधानसभा का विशेष सत्र बुलाना पड़ा। महज 15 मिनट का यह सत्र संवैधानिक बाध्यता के कारण बुलाया गया।

राज्य विधानसभा का यह विशेष सत्र सामाजिक कार्यकर्ता एड्रिस रोड्रिज की याचिका पर बुलाया गया। उन्होंने बांबे हाई कोर्ट की गोवा पीठ में याचिका दी थी कि संविधान के अनुच्छेद 174 के अंतर्गत राज्य में विधानसभा सत्र बुलाया जाना चाहिए।

अनुच्छेद 174 (1) के मुताबिक, विधानसभा के दो सत्रों के बीच छह महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। गोवा में विधानसभा का पिछला सत्र 31 अगस्त को संपन्न हुआ था। इस आधार पर 28 फरवरी से पहले विधानसभा सत्र बुलाया जाना आवश्यक था। हालांकि राज्य में अगली विधानसभा के लिए मतदान चार फरवरी को संपन्न हो चुका है। चुनाव परिणाम 11 मार्च को आएगा। इस संवैधानिक बाध्यता को देखते हुए मंगलवार को 15 मिनट का विधानसभा सत्र बुलाया गया। मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पारसेकर ने कहा, यह एक तकनीकी सत्र था। राज्य में नई सरकार का भाग्य ईवीएम में बंद हो चुका है, बावजूद इसके पुरानी सरकार की ओर से सत्र बुलाना संविधान के विरुद्ध है, ऐसा मेरा मानना है। इसी कारण मैं इसके पक्ष में नहीं था। हालांकि कुछ स्वनामधन्य संविधान विशेषज्ञों का दबाव था कि संवैधानिक नियम की पूर्ति के लिए सत्र बुलाना आवश्यक है। राज्यपाल मृदुला सिन्हा ने विशेष सत्र में किसी प्रकार के नीतिगत बयान से परहेज किया। हालांकि विपक्षी दल कांग्रेस का कहना है कि सत्र के दौरान विपक्ष के नेता के बोलने से पहले ही राष्ट्रगान बजा दिया गया। इस पर विधानसभा अध्यक्ष अनंत शेठ ने कहा कि यह विशेष सत्र था और नियम इसमें विपक्ष के नेता को कोई मुद्दा उठाने की अनुमति नहीं देते।

नगा शांति समझौते की विषय वस्तु सार्वजनिक करे मोदी सरकार - राहुल

इंफाल

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को केंद्र से मांग की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस नगा शांति समझौते पर दस्तखत किए हैं, उसकी विषय-वस्तु को सार्वजनिक किया जाए। उन्होंने मोदी पर यह आरोप भी मढ़ा कि वह जहां कहीं जाते हैं, वहां नफरत और झूठ फैलाते हैं। यहां एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा, केंद्र ने नगा शांति समझौते पर दस्तखत किए हैं, लेकिन इसकी विषय-वस्तु के बारे में किसी को नहीं पता। यहां तक कि मणिपुर के मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह और राज्य सरकार को भी इसके बारे में नहीं पता। मणिपुर के लोगों को समझौते की विषय-वस्तु के बारे में अंधेरे में क्यों रखा जा रहा है?

राहुल ने कहा, नरेंद्र मोदी जहां कहीं जाते हैं, वह झूठ, नफरत और भाइयों के बीच दुश्मनी फैलाते हैं। वह झूठे वादे करते हैं। उन्होंने इबोबी सिंह सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के बेबुनियाद आरोप लगाए थे। वह हमेशा गलत दावे करते हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष के सुर में सुर मिलाते हुए इबोबी सिंह ने भी मांग की कि समझौते की विषय-वस्तु को सार्वजनिक किया जाए और इसे

इंटरनेट पर डाला जाए। उन्होंने रैली में कहा, उन्हें (केंद्र को) इसे वेबसाइट पर डालना चाहिए, ताकि लोग देख सकें और फैसला कर सकें कि इससे राज्य (मणिपुर) की क्षेत्रीय अखंडता प्रभावित होगी कि नहीं। समझौते की रूपरेखा (फ्रेमवर्क एग्रीमेंट) करार दिए जा रहे नगा शांति समझौते पर केंद्र और एनएससीएन-आईएम ने अगस्त 2015 में दस्तखत किए थे। करीब 18 साल तक चली 80 से ज्यादा दौर की वार्ता के बाद समझौते पर दस्तखत किए गए। पहली सफलता 1997 में उस वक्त मिली जब प्रतिबंधित संगठन के साथ संघर्ष विराम समझौते पर दस्तखत किए गए।

आगामी चार और आठ मार्च को होने जा रहे मणिपुर विधानसभा चुनाव में नगा शांति समझौते की विषय-वस्तु एक बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस केंद्र में सत्ताधारी भाजपा पर मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता से समझौता करने का आरोप लगा रही है, जबकि भाजपा इस आरोप को नकार रही है। बीती 25 फरवरी को इंफाल में चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर की कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया था कि वह नगा समझौते पर दुष्प्रचार फैला रही है।। मोदी ने कहा था कि समझौते में ऐसा कुछ नहीं है जिससे मणिपुर के हित प्रभावित हों।

मोदी ने मुख्यमंत्री इबोबी सिंह पर करारा हमला बोलते हुए आरोप लगाया था कि वह सबसे भ्रष्ट सरकार चला रहे हैं। राहुल ने कहा कि सिर्फ कांग्रेस की सरकार ही मणिपुर को विकास एवं समृद्धि के रास्ते पर ले जा सकती है। नोटबंदी के मुद्दे पर कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कहा, नोटबंदी से इस देश के गरीबों की रोजी-रोटी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। किसान और दिहाड़ी मजदूर इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं।

रामजस कॉलेज विवाद

एबीवीपी के खिलाफ आइसा ने निकाला विरोध मार्च

कैंपस में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात

नई दिल्ली

रामजस कॉलेज में बीते दिनों हुई हिंसा के मद्देनजर एबीवीपी के खिलाफ दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में मार्च निकाला गया। बता दें कि एबीवीपी ने सोमवार को यहां तिरंगा मार्च निकाला था। वामदलों से संबद्ध आइसा और अन्य छात्र संगठनों के (डीयू और जेएनयू) सदस्यों ने इस मार्च में शामिल होकर अपना विरोध दर्ज कराया।

दिल्ली यूनिवर्सिटी में एआईएसए के इस सेव डीयू मार्च को लेकर कैंपस में काफी कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बलों को तैनात किया गया। एबीवीपी के खिलाफ निकाले गए इस मार्च में जेएनयू और डीयू के छात्र भी शामिल हुए, वहीं मिरांडा हाउस कॉलेज के बाहर भी एबीवीपी के खिलाफ प्रदर्शन किया गया।

एजेंसी के अनुसार, दिल्ली विश्वविद्यालय, जेएनयू और जामिया के सैकड़ों छात्र और शिक्षक आज एबीवीपी के विरोध को दबाने के खिलाफ सड़कों पर उतरे। छात्रों ने पोस्टर ले रखे थे, जिन पर संदेश लिखा था, आपका राष्ट्रवाद हमारे लोकतंत्र से ऊपर नहीं है। नॉर्थ कैंपस से कला संकाय की इमारत की तरफ जाने वाली सड़क पर आयोजित इस मार्च में प्रदर्शनकारी छात्रों में मुख्य रूप से एआईएसए जैसे वाम संगठन के छात्र शामिल थे। इन्होंने नारेबाजी भी की। खालसा कॉलेज के गेट से शुरू हुए इस मार्च के रास्ते में आने वाले कॉलेजों के दरवाजे बंद थे। पिछले हफ्ते रामजस कॉलेज में आयोजित एक कार्यक्रम के रद्द होने के बाद एबीवीपी और एआईएसए के बीच हुई हिंसक झड़प जैसी घटना दुबारा न हो इसके लिए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी।

दूसरी ओर, रामजस कॉलेज में बीते दिनों हुई हिंसा के बाद सोशल मीडिया पर छात्र संगठन एबीवीपी के खिलाफ अभियान शुरू करने वाली करगिल शहीद की बेटी गुरमेहर कौर ने पूरे मामले में विवाद बढ़ने के बाद कैंपेन से खुद को अलग कर लिया है।

गुरमेहर को रेप की धमकी के मामले में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है। कारगिल शहीद की बेटी के मामले के संबंध में अज्ञात लोगों के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई है। छात्रा को कथित तौर पर एबीवीपी के सदस्यों से बलात्कार की धमकियां मिल रही थीं। गुरमेहर कौर ने मंगलवार को ट्वीट कर कहा कि मैं इस अभियान से खुद को अलग कर रही हूं।

■ शेष पृष्ठ 2 पर

कंसास फायरिंग : सुषमा स्वराज ने अमेरिकी युवक की बहादुरी को सराहा

नई दिल्ली

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अमेरिका में गोलीबारी के दौरान बीच-बचाव करने वाले अमेरिकी नागरिक के जल्द ठीक होने की कामना की है और कहा कि भारत उनकी बहादुरी को सलाम करता है। सुषमा ने एक ट्वीट कर कहा, भारत इयान ग्रिलट की बहादुरी को सलाम करता है। जल्द ठीक होने की शुभकामनाएं। गौरतलब है कि कंसास के ओलेथ में एक बार में अमेरिकी नौसेना के एक पूर्व जवान एडम पुरिंटन द्वारा जाहिरा तौर पर घृणा अपराध के तहत की गयी गोलीबारी में श्रीनिवास कुचीबोतला की मौत हो गयी थी और एक अन्य भारतीय आलोक मदसानी घायल हो गये थे।

न्यायिक सेवा पर अटॉर्नी जनरल से मांगी राय

नई दिल्ली

सरकार ने अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन पर दो शीर्ष विधि अधिकारियों से राय मांगी है। यह मुद्दा राज्यों और न्यायपालिका के बीच मतभेद की वजह से 1960 के दशक से ही अधर में लटका है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद की अध्यक्षता में हाल में हुई एक बैठक में आइएएस और आइपीएस की तर्ज पर अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (एआइजीएस) के गठन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी और सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार से राय मांगने का फैसला किया गया। दोनों अधिकारियों ने विधि मंत्रालय के अन्य अधिकारियों के साथ 16 जनवरी की बैठक में हिस्सा लिया था। बैठक में एआइजेएस के गठन पर चर्चा हुई थी। नरेंद्र मोदी सरकार ने लंबे समय से लंबित इस प्रस्ताव को नए सिरे से आगे बढ़ाया है। हालांकि, इस मुद्दे पर राज्य सरकारों और संबंधित उच्च न्यायालयों की अलग-अलग राय है। इस मुद्दे पर अहम समस्या भाषा को माना जाता रहा है।

सपा का 24 घंटे बिजली देने का वादा सैफई और कुछ जगहों तक सिमट गया - पीयूष गोयल

नई दिल्ली

केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को प्रदेश सरकार के विकास पर सवाल उठाते हुए कहा कि सूबे में बिजली देने में भी भेदभाव किया जा रहा है। यह आरोप-प्रत्यारोप नहीं बल्कि तथ्यों पर आधारित है। मुरादाबाद सांसद कुंवर सर्वेश कुमार ने केंद्रीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने मामले को उठाया तो इसकी जांच करायी गयी। रिपोर्ट में कनेक्शन के साथ ही आपूर्ति में भेदभाव करने की तथ्य सामने आया।

भाजपा के चौकाघाट स्थित मीडिया सेल में प्रेसवार्ता में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जांच में पाया गया कि खास जाति और समुदाय बाहुल्य इलाके में बिजली का आवंटन किया गया और दूसरे समुदाय को इससे वंचित रखा गया। केंद्र ने भेदभाव बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए एफआईआर दर्ज करने की बात कही लेकिन राज्य सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। सपा के घोषणा पत्र में पूरे प्रदेश में 24 घंटे बिजली देने का वादा था लेकिन यह सैफई के साथ कुछ चुनिंदों जगहों तक ही सिमट कर रह गया है।

आईपीडीएस का और होगा विस्तार

आईपीडीएस योजना का आगामी दिनों में शहर के अन्य इलाकों में भी विस्तार किया जाएगा। स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। अंडरग्राउंड केबलिंग कार्य में देरी पर कहा कि आबादी को देखते हुए हम एक साथ काम नहीं करा सकते हैं क्योंकि यदि एक साथ काम शुरू हो जाए तो ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ सकती है। उन्होंने दावा किया आगामी ढाई सालों में आईपीडीएस के सभी कार्य पूरे कर लिए जाएंगे।

बिजली के मामले में यूपी सबसे पिछड़ा

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बिजली के मुद्दे पर यूपी सबसे पिछड़ा राज्य है। यहां एक करोड़ 80 लाख परिवार आज भी बिजली से वंचित हैं जबकि केंद्र ने बिजली उपलब्ध कराने के लिए 18000 करोड़ रुपये यूपी को आवंटित किया है, लेकिन प्रदेश सरकार अभी तक 4000 करोड़ ले पायी। क्योंकि फंड लेने के लिए प्रदेश सरकार यूटीलाइजेशन सर्टिफिकेट ही नहीं दे पायी।

24 क्या 14 घंटे भी बिजली आपूर्ति नहीं

अखिलेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गंगा की कसम खिलाने के बयान पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले शिवपुर सहित कई शहरी क्षेत्रों में आपूर्ति के आंकड़े बताते हैं कि इन इलाकों में 24 घंटे क्या, 14 घंटे भी बिजली नहीं मिल पाती है। उन्होंने कहा कि जिन जगहों पर मतदान खत्म हो चुका है वहां चुनाव के दौरान तो 24 घंटे बिजली देने का प्रयास किया गया, लेकिन वोट देने के चार घंटे बाद ही कटौती शुरू हो गयी।

■ शेष पृष्ठ 2 पर

300 सीटें जीतने का दावा करने वाले गठबंधन सरकार की बात करने लगे -अखिलेश

आजमगढ़

उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि कल तक विधानसभा चुनाव में 300 सीटें जीतने का दम भरने वाले मोदी और भाजपा के लोग अब गठबंधन की सरकार की बातें करने लगे हैं।

अखिलेश ने यहां सपा प्रत्याशियों के समर्थन में आयोजित चुनावी सभाओं में कहा कि पहले तो प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी के लोग कहते थे कि भाजपा 300 सीटें जीतकर आएगी। मउ तक चुनाव आते-आते वे कह रहे हैं कि गठबंधन की सरकार बनेगी। आजमगढ़ में मोदी इसलिये नहीं आये क्योंकि उन्हें मालूम हो गया है कि यहां की सभी 10 सीटें सपा जीत रही है।

सपा अध्यक्ष का इशारा प्रधानमंत्री मोदी द्वारा मउ में अपनी रैली में दिये गये उस बयान की तरफ था, जिसमें उन्होंने सपा और बसपा पर त्रिशंकु विधानसभा बनाने का खेल खेलने का आरोप लगाया था।

इसके अलावा केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री रामदास आठवले ने भी गोरखपुर में कहा था कि अगर भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो बसपा को उसे समर्थन देना चाहिये। अखिलेश ने चुनाव के दौर से गुजर चुके क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित किये जाने के प्रधानमंत्री के आरोप को भी गलत बताते हुए कहा कि ऐसी बातें करने से पहले मोदी को पहले चरण के चुनाव से गुजरे किसी भी जिले में बिजली आपूर्ति की स्थिति का पता लगाना चाहिये था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा विधानसभा चुनाव उत्तरप्रदेश के भविष्य का चुनाव है।

जाहिर है कि इससे जनता का भविष्य भी जुड़ा है। मैंने भाजपा और प्रधानमंत्री से कहा कि जिस जिले में उनका कार्यक्रम हो तो बताएं कि वहां के लिये उनकी सरकार ने क्या काम किया है। तीन साल गुजर गये, मगर कोई भी काम बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाये।

उन्होंने गम्भीर आरोप लगाते हुए कहा कि केन्द्र सरकार नोटबंदी के बाद सामने आये कालेधन के आंकड़ों को छुपाकर बड़े लोगों को लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रही है। अखिलेश ने कहा कि प्रधानमंत्री और भाजपा के लोग नोटबंदी के नाम पर देश को गुमराह कर रहे हैं।

■ शेष पृष्ठ 2 पर

सेना पेपर लीक मामला

शिवसेना ने मनोहर परिकर पर साधा निशाना

मुंबई

शिवसेना ने सेना में भर्ती का प्रश्नपत्र लीक होने को लेकर रक्षामंत्री मनोहर परिकर पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा को इस पूरी घटना की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जिसने सरकार की छवि खराब की है।

शिवसेना ने पार्टी के मुखपत्र सामना में छपे संपादकीय में कहा, विश्वविद्यालयों एवं अन्य परीक्षाओं के पेपर लीक होते थे, लेकिन अब सेना की भर्ती संबंधी प्रश्नपत्र भी लीक हो गया। जब जवान अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं, ऐसे में इस पेपर के लीक होने से सरकार की छवि खराब हो गई है। उसने कहा, मनोहर परिकर फिर से गोवा के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और वह पणजी से रक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे हैं, लेकिन कम से कम जब तक वह (रक्षा मंत्री के) पद पर हैं, उन्हें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। शिवसेना ने कहा कि यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है, इसलिए भाजपा को आगे आकर पेपर लीक की पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उसने कहा प्रधानमंत्री राष्ट्रवाद एवं बलिदान की बात करते हैं, लेकिन उनकी बातें हकीकत में तब्दील होती प्रतीत नहीं होतीं। यदि नोटबंदी में राष्ट्रवाद है तो सेना की भर्ती में भी ऐसा ही होना चाहिए। प्रश्नपत्र लीक कराने वाले रैकेट का शनिवार रात को भंडाफोड़ हुआ था जब महाराष्ट्र एवं गोवा में छापेमारी के बाद 18 लोग गिरफ्तार किए गए थे। तीन और लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन सभी को ठाणे की एक अदालत ने चार मार्च तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया है। प्रश्न पत्र लीक हो जाने के कारण 26 फरवरी को होने वाली इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया था।

मणिपुर सरकार पर अमित शाह ने लगाए भ्रष्टाचार के आरोप

इंफाल

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए राज्य सरकार को भी जमकर कोसा है। राज्य में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री इबोबी सिंह ने अधूरे प्रोजेक्ट्स का ही उदघाटन करवा दिया। इसके लिए उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी को यहां पर बुलाया। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार यहां के प्रोजेक्ट के लिए फंड को खा गई है।

अमित शाह ने कहा कि मणिपुर में खुद को मॉडल स्टेट बनाने की ताकत है। साथ ही उत्तर पूर्वी राज्यों के कई इलाके अपने आप में बेहद संपन्न हैं। गौरतलब है कि मणिपुर

विधानसभा चुनाव की 60 सीटों के के लिए दो चरणों में मतदान होगा। इसका पहला चरण 4 मार्च और दूसरा चरण 8 मार्च को होगा। 11 मार्च 2017 को चुनाव के परिणाम घोषित किए जाएंगे।

वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल 18 मार्च 2017 को समाप्त होगा। यही वजह है कि यहां पर पहले पीएम मोदी ने चुनावी सभा की थी और अब यहां पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे हैं।

बीते शनिवार को यहां पर पीएम मोदी ने भी एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया था। उन्होंने इस दौरान कहा था कि यदि भाजपा सत्ता में आती है तो यहां पर आर्थिक नाकेबंदी का दौर खत्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने 15 साल से सरकार चला रहे मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वह झूठ फैलाकर एक जनजाति को दूसरी जनजाति से लड़ाने का काम करते रहे हैं। चुनाव जीतने के लिए आम जनता को परेशान कर रहे हैं। बता दें कि कुछ माह पहले बनाए गए सात नए जिलों के विरोध में राज्य के एक नगा संगठन ने पिछले 100 दिनों से एक प्रमुख हाइवे को बंद कर रखा है।

भारत में स्पीड ब्रेकर की वजह से हर रोज दस लोगों की होती है मौत

नई दिल्ली

स्पीड ब्रेकर को लेकर जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में हर रोज दस लोगों की मौत की वजह स्पीड ब्रेकर होते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी इस रिपोर्ट में दर्ज आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2015 के दौरान देश भर में करीब 11000 लोगों की जान सड़क हादसों में गई, जिसमें से करीब 3409 मौतों की वजह स्पीड ब्रेकर बने थे। रिपोर्ट के मुताबिक देश में हर रोज होने वाले 30 में 10 हादसे की वजह स्पीड ब्रेकर ही होते हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2015 में मध्यप्रदेश, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में करीब 6073 मौतों की वजह स्पीड ब्रेकर ही थे। यह इस दौरान हुए हादसों का करीब पचास फीसद है। अकेले यूपी, तमिलनाडु और कर्नाटक में ही इस दौरान करीब 1794 मौतों के पीछे भी स्पीड ब्रेकर ही थे। अकेले यूपी में ही वर्ष 2014 में 1753 और 2015 में 990 मौत स्पीड ब्रेकर की वजह से हुई थीं। इतना ही नहीं इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि हत्या के मामलों में यूपी देश का नंबर वन राज्य है।

नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो के मुताबिक देश भर में वर्ष 2015 के दौरान कुल 32127 हत्या के मामले दर्ज किए गए, जिसमें से करीब 15 फीसद मामले अकेले यूपी में ही दर्ज किए गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर में वर्ष 2014 और 2015 के दौरान 15 और 17 मौत की वजह सड़कों पर बने स्पीड ब्रेकर थे, वहीं इस दौरान यहां सेना के करीब 32 और 33 जवान भी मारे गए थे। हालांकि रिपोर्ट यह भी बताती है कि वर्ष 2015 में उत्तर प्रदेश के अंदर 2014 के मुकाबले कम एक्सीडेंट और मौत हुई हैं। ऐसा ही कुछ ट्रेंड बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात और कर्नाटक में भी देखने को मिलता है।

सड़क हादसे या फिर यूं कहें कि स्पीड ब्रेकर को लेकर बनाई गई सरकारी एजेंसी इंडियन रोड कांग्रेस के मुताबिक देश भर में बने स्पीड ब्रेकर में से ज्यादातर में नियमों की अनदेखी की गई है। उनके मुताबिक जो स्पीड ब्रेकर ट्रकों के लिहाज से सही होते हैं वह मोटरसाइकिलों के लिए सही नहीं होते हैं ओर जो मोटरसाइकिलों के लिए ठीक होते हैं वह ट्रंकों के लिहाज से सही नहीं होते हैं।